राष्ट्रीय हिन्दी मासिक

एक्सपर्ट टाइम्स

RNI No.- DLBIL/26/A3806

www.xperttimes.com

नईदिल्ली, रविवार, 01 नवम्बर 2026 से 30 नवम्बर 2026 तक वर्ष– 01 अंक–05 पृष्ठ–04 मासिक मूल्य– 50 रुपए



पेज नं-3

अनुष्का शर्मा फिर सुर्खियों का हिस्सा

मुंबई कोस्टल रोड पर BMW हादसा: बैरियर तोड़कर पुल से नीचे गिरी कार, 3 छात्रों की मौत

अंजली सिंह

मुंबई। कोस्टल रोड पर रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन युवाओं की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा उस समय हुआ जब तेज रफ्तार BMW कार सड़क किनारे लगे बैरियर को तोड़ते हुए पुल से नीचे जा गिरी। इस पूरी घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कार को तेज गति से आते और फिर बैरियर से टकराकर नीचे गिरते हुए देखा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक, हादसा सुबह करीब 5:20 बजे हुआ। BMW मरीन ड्राइव की तरफ से हाजी अली की दिशा में जा रही थी। इसी दौरान लोटस जेट्टी के पास, लाला लाजपत राय कॉलेज के सामने कार अचानक नियंत्रण से बाहर हो गई। इसके बाद कार सड़क के किनारे बने बैरियर से टकराई और उसे तोड़ते हुए पुल से नीचे जा गिरी। CCTV फुटेज हादसे की गंभीरता को साफ तौर पर दिखाता है। फुटेज में BMW तेज गति से सड़क पर आगे बढ़ती दिखाई देती है। कुछ ही क्षण बाद वाहन बैरियर से टकराता है और ऊंचाई से नीचे निमार्णाधीन पार्किंग क्षेत्र में जा गिरता है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के समय इटह में चार लोग सवार थे। दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे। सभी घायलों को इलाज के लिए मुंबई के नायर अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई गई।



मृतकों में 21 वर्षीय शनाय गज्जल और 17 वर्षीय धैर्य सेठ की पहचान की गई है। तीसरे मृतक की उम्र करीब 25 वर्ष बताई गई है और शुरूआती रिर्पोटों में उसकी पहचान की प्रक्रिया जारी थी। हादसे में घायल एक अन्य व्यक्ति की उम्र करीब 20 वर्ष बताई गई है और उसे अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि आखिर इटह चालक का वाहन पर नियंत्रण कैसे खत्म हुआ। पुलिस CCTV फुटेज के साथ-साथ दुर्घटनास्थल, वाहन की स्थिति और सड़क पर मौजूद अन्य परिस्थितियों की भी जांच कर रही है। हादसे में कार की रफ्तार भी जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शुरूआती रिर्पोटों में BMW के तेज गति से चलने की बात सामने आई है, लेकिन वाहन की वास्तविक गति और दुर्घटना में उसकी भूमिका जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। मुंबई कोस्टल रोड शहर की महत्वपूर्ण परिवहन परियोजनाओं में से एक है। इसका उद्देश्य दक्षिण मुंबई और शहर के पश्चिमी हिस्सों के बीच यात्रा को आसान बनाना और प्रमुख सड़कों पर यातायात का दबाव कम करना है। इस मार्ग पर अलग-अलग हिस्सों के लिए गति सीमा निर्धारित है। मुख्य कैरिजवे पर अधिकतम गति सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई है, जबकि रैंप, मोड़ और अन्य हिस्सों पर गति सीमा कम रहती है। पुलिस अब यह भी जांच सकती है कि हादसे से पहले वाहन की दिशा और गति में कोई असामान्य बदलाव हुआ था या नहीं। CCTV फुटेज इस जांच में अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि इससे दुर्घटना से पहले कार की गतिविधियों को समझने में मदद मिलेगी।

फिलहाल पुलिस ने हादसे की अंतिम वजह को लेकर कोई निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं किया है। जांच के दौरान वाहन की तकनीकी स्थिति, सड़क की परिस्थितियों और CCTV रिकॉर्डिंग समेत सभी उपलब्ध साक्ष्यों की जांच की जा रही है। इस हादसे ने एक बार फिर तेज रफ्तार वाहन चलाने और सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। आधुनिक और नियंत्रित सड़कों पर भी वाहन चलाते समय निर्धारित गति सीमा और यातायात नियमों का पालन बेहद जरूरी है। मुंबई कोस्टल रोड पर हुए इस हादसे में तीन युवाओं की जान चली गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। अब पुलिस की जांच से यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि BMW किस परिस्थिति में नियंत्रण से बाहर हुई और आखिर वह बैरियर तोड़कर पुल से नीचे कैसे जा गिरी।

दिल्ली के आस्था कुंज पार्क में नाबालिग से कथित गैंगरेप, पुलिसकर्मी बनकर पहुंचे थे आरोपी

जितेन्द्र कुमार

नई दिल्ली। दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के कालकाजी मंदिर के पास स्थित आस्था कुंज पार्क में एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ कथित गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक, तीन युवकों ने कथित तौर पर खुद को पुलिसकर्मी बताकर लड़की और उसके नाबालिग दोस्त को धमकाया। आरोप है कि इसके बाद तीनों ने लड़की के साथ यौन हिंसा की। मामले की सूचना मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपियों की तलाश के लिए कई टीमें गठित कीं।

पुलिस के अनुसार, पीड़िता सोमवार शाम अपने 17 वर्षीय दोस्त के साथ कालकाजी मंदिर गई थी। दोनों करीब शाम 7 बजे मंदिर पहुंचे थे। दर्शन के बाद दोनों पास स्थित आस्था कुंज पार्क चले गए। बताया गया है कि करीब 7:30 बजे दोनों पार्क में मौजूद थे, तभी तीन युवक वहां पहुंचे। पुलिस के मुताबिक, तीनों आरोपियों की उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष के बीच बताई गई है। आरोप है कि उन्होंने खुद को पुलिसकर्मी बताया और दोनों किशोरों को धमकाना शुरू कर दिया। पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि आरोपियों ने उसके दोस्त को अपने कब्जे में रखा और उसके साथ मारपीट की। इसके बाद तीनों आरोपियों ने कथित तौर पर लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी मिलने के बाद करीब 8:45 बजे पुलिस को PCR कॉल मिली। सूचना मिलते ही अमर कॉलोनी थाना पुलिस की टीम आस्था कुंज पार्क पहुंची। पुलिस ने मौके पर पीड़िता और उसके दोस्त को पाया और उनसे घटना के संबंध में जानकारी ली। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया और उसका बयान दर्ज किया। घटनास्थल की भी जांच की गई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से उपलब्ध साक्ष्यों को जुटाने की प्रक्रिया शुरू की। जांचकताओं ने आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगालनी शुरू की, ताकि आरोपियों की पहचान और उनकी गतिविधियों का पता लगाया जा सके।

नाबालिग होने के कारण मामले में पॉक्सो के तहत भी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपियों ने पीड़ितों को किस तरह धमकाया और खुद को पुलिसकर्मी बताने के पीछे उनकी क्या भूमिका थी। जांच के दौरान पुलिस को एक संदिग्ध के बारे में जानकारी मिली, जिसकी पहचान रिपोर्टों में आसिफ के रूप में की गई है। पुलिस के अनुसार, उसे अमर कॉलोनी इलाके में DM Office Road के पास पकड़ने की कोशिश की गई। इसी दौरान आरोपी ने कथित तौर पर पुलिस टीम पर गोली चला दी। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने तीन राउंड फायर किए। इस दौरान एक गोली हेड कांस्टेबल राजेश की बुलेटप्रूफ जैकेट से टकराई। पुलिस के मुताबिक, इसके बाद पुलिसकर्मी ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। एक गोली आरोपी के पैर में लगी। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया और इलाज के लिए AIIMS Trauma Centre ले जाया गया। घटना के इस हिस्से की भी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए हैं। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि मुठभेड़ की परिस्थितियां क्या थीं और आरोपी के पास हथियार कहां से आया। वहीं, मामले में शामिल बताए जा रहे दो अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस आसपास के इलाकों की CCTV फुटेज की जांच कर रही है और संदिग्धों के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। इस मामले में पुलिस का मुख्य उद्देश्य पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट, CCTV फुटेज और अन्य फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर घटना की पूरी कड़ी को स्थापित करना है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि तीनों आरोपियों की आपस में क्या भूमिका थी और घटना से पहले तथा बाद में उनकी गतिविधियां क्या थीं। चूंकि मामला एक नाबालिग से जुड़ा है, इसलिए कानून के तहत पीड़िता की पहचान सार्वजनिक नहीं की जा सकती। पुलिस ने भी मामले की जांच को संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ाने की बात कही है। फिलहाल एक संदिग्ध को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी सामने आई है, जबकि दो अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही घटना से जुड़े सभी तथ्यों और आरोपियों की भूमिका स्पष्ट हो सकेगी। मामले में लगाए गए आरोपों का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से होगा।

पुलिस के मुताबिक, तीनों आरोपियों की उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष के बीच बताई गई है। आरोप है कि उन्होंने खुद को पुलिसकर्मी बताया और दोनों किशोरों को धमकाना शुरू कर दिया। पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि आरोपियों ने उसके दोस्त को अपने कब्जे में रखा और उसके साथ मारपीट की।

रूस के ड्रोन हमले से यूक्रेन के निप्रो रेलवे स्टेशन पर मची तबाही, 14 लोगों की मौत

जितेन्द्र कुमार

यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध के बीच एक बार फिर आम नागरिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। गुरुवार, 29 अक्टूबर 2026 को यूक्रेन के निप्रो शहर के मुख्य रेलवे स्टेशन पर रूसी ड्रोन हमले में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। शुरूआती रिर्पोटों में मृतकों की संख्या 13 बताई गई थी, लेकिन बाद में अधिकारियों ने इसे बढ़ाकर 14 कर दिया। इस हमले के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए आपातकालीन सेवाओं को लगाया गया।



प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन को बनाया निशाना

यूक्रेन की सरकारी रेलवे कंपनी उक्रजालिजनित्सिया के अनुसार, रूसी जेट-संचालित ड्रोन ने निप्रो रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म को निशाना बनाया। हमले के समय वहां निप्रो से जापोरिज्जिया जाने वाली ट्रेन नंबर 866 खड़ी थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने बताया कि प्लेटफॉर्म पर एक सामान्य यात्री ट्रेन और एक नियमित यात्री सेवा मौजूद थी। हमले के समय स्टेशन पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, खतरे को लेकर चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन इसके बावजूद कई यात्री प्लेटफॉर्म पर ही थे। ड्रोन के हमले ने यात्रियों को संभलने का पर्याप्त मौका नहीं दिया और कई लोग इसकी चपेट में आ गए। निप्रो के क्षेत्रीय प्रशासन के प्रमुख ओलेक्सांद्र हांझा ने शुरूआत में 13 लोगों की मौत की जानकारी दी थी। बाद में मृतकों की संख्या बढ़कर 14 हो गई। अधिकारियों ने बताया कि कई घायलों की हालत गंभीर थी और उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता थी।

राहत और बचाव कार्य में जुटी टीमें

हमले की जानकारी मिलते ही आपातकालीन सेवाओं, चिकित्सा कर्मियों और पुलिस की टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और राहतकर्मियों ने प्रभावित इलाके में बचाव कार्य शुरू किया। इस हमले ने स्टेशन पर मौजूद यात्रियों और उनके परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया। रेलवे स्टेशन आमतौर पर लोगों के आने-जाने, अपने परिजनों से मिलने और काम के सिलसिले में यात्रा करने का स्थान होता है। लेकिन युद्ध के दौरान ऐसे सार्वजनिक स्थान भी लगातार खतरे का सामना कर रहे हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हमले की निंदा करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों से रूस के खिलाफ दबाव बढ़ाने और यूक्रेन की सुरक्षा मजबूत करने की अपील भी की।

युद्ध के बीच रेलवे नेटवर्क पर बढ़ता खतरा

यूक्रेन का रेलवे नेटवर्क देश के परिवहन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हवाई यातायात बंद रहने के कारण ट्रेनें यात्रियों और सामान को एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाती हैं। लाखों लोग रोजमर्रा की जरूरतों, काम और परिवार से मिलने के लिए रेल सेवाओं पर निर्भर हैं। हालांकि, रूस के हमलों और ड्रोन संबंधी चेतावनियों के कारण रेलवे संचालन लगातार प्रभावित हो रहा है।

यूक्रेन की रेलवे कंपनी के मुताबिक, सितंबर महीने में ड्रोन हमलों के खतरे के कारण 5,800 से अधिक ट्रेन सेवाओं में यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए निकासी की आवश्यकता पड़ी थी। बार-बार मिलने वाली चेतावनियों के कारण यात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान अचानक ट्रेन से उतरना पड़ सकता है। इससे न केवल यात्रा में देरी होती है, बल्कि लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता भी बढ़ जाती है।

दिल्ली में SIR प्रक्रिया पर उठे सवाल, मुस्लिम मतदाताओं के अधिक अनुपात में फ्लैग होने से बढ़ी चिंता

जितेन्द्र कुमार

नई दिल्ली: दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। मतदाता सूची के ड्राफ्ट डेटा के विश्लेषण में सामने आए आंकड़ों के अनुसार, मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा अनुपात उन मतदाताओं में शामिल है, जिनके रिकॉर्ड में कथित तौर पर तार्किक विसंगतियां पाई गई हैं। इन आंकड़ों ने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सभी पात्र नागरिकों के मतदान अधिकारों को लेकर सवाल खड़े किए हैं।

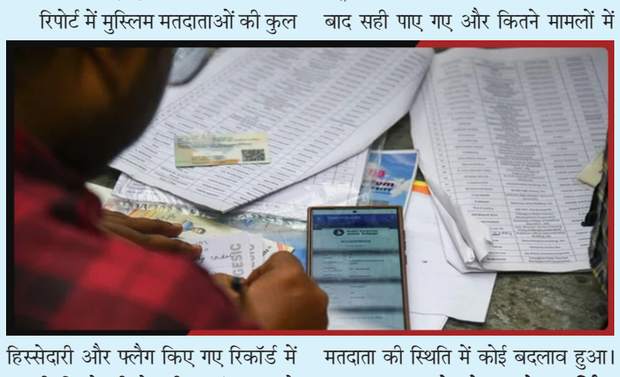
14 अक्टूबर 2026 को सामने आई रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली की ड्राफ्ट मतदाता सूची में मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी लगभग 13.6 प्रतिशत बताई गई है। वहीं, तार्किक विसंगतियों के आधार पर फ्लैग किए गए मतदाताओं में उनकी हिस्सेदारी लगभग 20.3 प्रतिशत दर्ज की गई। इसके अलावा, परिवार के सदस्यों की संख्या और उनकी उम्र से जुड़े पांच मानदंडों के तहत फ्लैग किए गए लगभग 6.75 लाख मतदाताओं में मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी करीब 30 प्रतिशत बताई गई है। इन आंकड़ों ने यह सवाल उठाया है कि मतदाता रिकॉर्ड की जांच के लिए इस्तेमाल किए जा रहे मानदंड सभी समुदायों पर समान रूप से लागू हो रहे हैं या नहीं। हालांकि, केवल इन आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि किसी समुदाय को जानबूझकर निशाना बनाया गया है। इसके लिए जांच प्रक्रिया, संबंधित रिकॉर्ड और अंतिम निर्णयों का विस्तृत विश्लेषण आवश्यक है।

क्या है SIR प्रक्रिया?

SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाना है। इस प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं के रिकॉर्ड की जांच की जाती है, पुरानी जानकारी से उनका मिलान किया जाता है और उन प्रविष्टियों की पहचान की जाती है जिनमें किसी तरह की विसंगति या जानकारी की कमी दिखाई देती है। दिल्ली की ड्राफ्ट मतदाता सूची में लगभग 97.54 लाख मतदाता शामिल बताए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, करीब 33.12 लाख मतदाताओं को अलग-अलग श्रेणियों में नोटिस या अतिरिक्त सत्यापन के लिए फ्लैग किया गया। इनमें पुराने पुनरीक्षण रिकॉर्ड से मिलान न होने वाले मतदाता और तार्किक विसंगतियों वाले रिकॉर्ड भी शामिल हैं। चुनाव प्रक्रिया में सही मतदाता सूची का होना जरूरी है, लेकिन किसी रिकॉर्ड में गड़बड़ी मिलने का अर्थ अपने आप यह नहीं है कि संबंधित व्यक्ति मतदान के योग्य नहीं है। कई बार नाम, उम्र, पारिवारिक संबंध या पुराने दस्तावेजों में अंतर होने के कारण भी रिकॉर्ड की दोबारा जांच करनी पड़ सकती है।

मुस्लिम मतदाताओं से जुड़े आंकड़ों पर क्यों उठ रहे हैं सवाल?

रिपोर्ट में मुस्लिम मतदाताओं की कुल



हिस्सेदारी और फ्लैग किए गए रिकॉर्ड में उनकी हिस्सेदारी के बीच अंतर सामने आया है। यही अंतर इस पूरे मामले में चर्चा का प्रमुख विषय बना हुआ है। विशेष रूप से परिवार के सदस्यों की संख्या और उम्र से जुड़े मानदंडों के तहत मुस्लिम मतदाताओं की लगभग 30 प्रतिशत हिस्सेदारी पर सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञों के लिए यह समझना महत्वपूर्ण होगा कि क्या इन मानदंडों के कारण किसी खास समूह के रिकॉर्ड में अधिक विसंगतियां सामने आ रही हैं या इसके पीछे डेटा की गुणवत्ता, पुराने रिकॉर्ड के मिलान अथवा अन्य प्रशासनिक कारण हैं। इन सवालों का जवाब पाने के लिए केवल फ्लैग किए गए मतदाताओं की संख्या देखना पर्याप्त नहीं होगा। यह भी जानना जरूरी है कि कितने मामलों में वास्तविक त्रुटियां पाई गईं, कितने रिकॉर्ड सामान्य स्पष्टीकरण के बाद सही पाए गए और कितने मामलों में मतदाता की स्थिति में कोई बदलाव हुआ।

चुनाव आयोग के सामने पारदर्शिता की चुनौती

मतदाता सूची की जांच में तकनीक की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयोग के ERONET सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल रिकॉर्ड में तार्किक विसंगतियों की पहचान के लिए किया गया। हालांकि, सॉफ्टवेयर द्वारा किसी रिकॉर्ड को फ्लैग करना और किसी मतदाता की पात्रता पर अंतिम निर्णय लेना अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। ऐसी स्थिति में पारदर्शिता बेहद जरूरी है। चुनाव आयोग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि किन मानदंडों के आधार पर रिकॉर्ड को फ्लैग किया जाता है, उसके बाद संबंधित मतदाता की जानकारी की जांच कैसे होती है और मतदाता को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कौन-से विकल्प उपलब्ध हैं। यदि किसी रिकॉर्ड में त्रुटि है, तो उसे सुधारने की प्रक्रिया सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। मतदाताओं को यह जानकारी मिलनी चाहिए कि उनसे कौन-से दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, उन्हें जवाब देने के लिए कितना समय दिया गया है और किसी निर्णय से असहमति होने पर वे किस प्रक्रिया के तहत अपना पक्ष रख सकते हैं।

पात्र मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा जरूरी

लोकतंत्र में मतदान का अधिकार बेहद महत्वपूर्ण है। मतदाता सूची को सही बनाए रखना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण कोई पात्र मतदाता अनावश्यक परेशानी का सामना न करे। पुराने दस्तावेजों में नाम की वर्तनी का अंतर, अधूरी जानकारी या परिवार के सदस्यों की उम्र से जुड़ी विसंगतियां अपने आप में किसी व्यक्ति की अपात्रता का प्रमाण नहीं हैं। ऐसे मामलों में संबंधित परिस्थितियों को समझना और नियमों के अनुसार निष्पक्ष निर्णय लेना आवश्यक है।

एटा में पुलिस मुठभेड़ में एक लाख का इनामी बदमाश वीरेंद्र ढेर

सर्राफा व्यापारी से लूट के मामले में था वांछित, मुठभेड़ में सिपाही सतपाल भी घायल

शिवम सोलंकी

एटा। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में थाना कोतवाली नगर और थाना पिलुआ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस के अनुसार, मुठभेड़ में एक लाख रुपये का इनामी बदमाश वीरेंद्र गोली लगने से घायल हो गया। उसे तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ में थाना पिलुआ में तैनात सिपाही सतपाल भी गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने घटनास्थल से एक अवैध पिस्टल, जिंदा व खोखा कारतूस तथा बिना नंबर प्लेट की नीली अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की है।

पुलिस के मुताबिक, मृतक आरोपी के खिलाफ विभिन्न जनपदों में करीब 53 मुकदमे दर्ज थे। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुखबिर से सूचना मिली कि थाना अलीगंज क्षेत्र में सर्राफा व्यापारी से लूट की घटना में वांछित एक लाख रुपये का इनामी बदमाश वीरेंद्र अपने साथी के साथ सुन्ना नहर के पास किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा है। सूचना मिलने पर कोतवाली नगर पुलिस ने थाना पिलुआ पुलिस को अवगत कराया और अपनी टीम के साथ माया पैलेस के पास चेकिंग शुरू कर दी। इसी दौरान आगरा चुंगी की ओर से निधौली रोड की तरफ बिना नंबर प्लेट की नीली अपाचे मोटरसाइकिल आती दिखाई दी, जिस पर दो व्यक्ति सवार थे।

पुलिस टीम ने मोटरसाइकिल सवारों को रोकने का प्रयास किया तो वे सुन्ना नहर की पटरी की ओर भागने लगे। पुलिस ने उनका पीछा किया। पुलिस के अनुसार, इसी दौरान मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें थाना पिलुआ में तैनात सिपाही सतपाल घायल हो गया। इसके बाद पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। घटनास्थल पर बदमाशों की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। पुलिस ने घायल सिपाही सतपाल और घायल बदमाश को तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने घायल बदमाश को मृत घोषित कर दिया।

दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। पुलिस ने घटनास्थल से एक अवैध 32 बोर पिस्टल, 32 बोर के तीन जिंदा कारतूस, 32 बोर के सात खोखा कारतूस, 315 बोर के तीन खोखा कारतूस, बिना नंबर प्लेट की एक नीली अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस के अनुसार, वीरेंद्र का आपराधिक इतिहास लंबा रहा है। उसके खिलाफ एटा, मैनपुरी, आगरा, इटावा और फिरोजाबाद समेत विभिन्न जनपदों में करीब 53 मुकदमे दर्ज होने की जानकारी दी गई है।

इनमें लूट, चोरी, हत्या, जानलेवा हमले, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के मामले शामिल हैं।

इस कार्रवाई में थाना कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र पंवार अपनी टीम के साथ तथा थाना पिलुआ के थानाध्यक्ष संदीप राणा अपनी टीम के साथ शामिल रहे।



संपादकीय

प्रशासनिक सुधारों को आगे बढ़ाने का समय

विकसित राजस्थान-2047' के लक्ष्य की दिशा में प्रशासनिक रोडमैप को गति देते हुए राजस्थान के मुख्य सचिव ने बीते दिनों भारतीय गुणवत्ता परिषद यानी क्यूसीआइ को शासन के छह विभागों के गहन संस्थागत परीक्षण का जिम्मा सौंपा है। इस कवायद का उद्देश्य कार्यप्रणालियों का विस्तृत खाका तैयार करना, विभागीय प्राथमिकताओं के अनुरूप मौजूदा मानव संसाधन की समीक्षा करना, अंतर-विभागीय दोहराव को समाप्त करना और प्रशासनिक पदानुक्रम के प्रत्येक स्तर पर स्पष्ट जवाबदेही सुनिश्चित करना है।अरुणाचल प्रदेश भी 2025 में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कर चुका है। केरलम ऐसी चार कवायदें पहले ही पूरी कर चुका है। यह रुझान दर्शाता है राज्यों ने अपनी प्रशासनिक मशीनरी को चुस्त-दुरुस्त बनाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। जबकि केंद्र सरकार ने 2009 के बाद से ऐसी कोई पहल नहीं की है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि केंद्र सरकार ने 'विकसित भारत' का नारा तो गढ़ा है, लेकिन वह अपने स्तर पर इस दिशा में कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है?कई कसौटियों पर प्रशासनिक सुधार आवश्यक ही नहीं, अपितु अपरिहार्य हो गए हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि सरकारी परियोजनाएं भारी लेट-लतीफी की शिकार हैं। केंद्रीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधिकारिक निगरानी रिपोर्ट दर्शाती है कि 458 परियोजनाओं की स्वीकृत लागत में 5.71 लाख करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त बढ़ोतरी हो गई है। ये परियोजनाएं कई महीनों से लेकर दशकों की देरी तक खिंच चुकी हैं। सुधारों की राह में इस पहलू को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि सरकारें सबसे बड़ी मुकदमेबाज बन गई हैं।वर्ष 2025 के अंत तक अदालतों में लंबित 5.39 करोड़ मुकदमों में केंद्र और राज्य सरकारें ही एक पक्ष हैं। स्थिति ऐसी बन गई है कि सरकार का एक विभाग ही दूसरे विभाग के खिलाफ अपील दायर कर रहा है और इस तकरार की कीमत आम नागरिकों के लंबित मामलों को चुकानी पड़ रही है।सुधारों की राह में तीसरी कसौटी योजनाओं को सुसंगत बनाने की है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं का दायरा कागजों पर तर्कसंगत बनाकर 130 से घटाकर 75 मूल श्रेणियों में समेटने का दावा तो किया गया, लेकिन हकीकत यही है कि 2025-26 में इनका बजट 5.4 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया। इनमें से तमाम योजनाएं दशकों से चली आ रही हैं, लेकिन उनकी उपयोगिता की व्यापक समीक्षा की सुध पहली बार पिछले साल ली गई है।चौथी कसौटी प्रशासनिक अधिकारियों से ही जुड़ी है। जहां सरकारों के सचिवालय तो बाबुओं से भरे हुए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अधिकारियों का भारी अभाव है। एक जनवरी 2025 तक आइएएस का लगभग हर पांचवां पद और आइएफएस का हर तीसरा पद खाली पड़ा था। इसका असर जिला स्तर और फील्ड पोस्टिंग में स्पष्ट दिखता है।पांचवीं कसौटी यही है कि मौजूदा व्यवस्था में किसी के भी काम की जवाबदेही या प्रदर्शन को समग्रता में नहीं आंका जाता। 'रिजल्ट्स फ्रेमवर्क डाक्युमेंट्स' की व्यवस्था ने एक समय सचिव स्तर के शीर्ष अधिकारियों को वार्षिक लक्ष्यों के लिए सीधे जवाबदेह बनाया था, जिनकी स्वतंत्र समीक्षा तीसरे पक्ष से कराई जाती थी। अपने दौर में करीब 80 विभागों को दायरे में लेने वाली यह व्यवस्था 2013-14 के बाद ठंडे बस्ते में डाल दी गई और इसका कोई विकल्प तक तैयार नहीं किया गया।स्पष्ट है कि जो व्यवस्था अपने अधिकारियों की कार्यक्षमता का ही हिसाब नहीं रख सकती तो वह उनके काम की कद्र कर उन्हें पुरस्कृत करेगी? ऐसे में ठोस नतीजों की उम्मीद बेमानी ही कही जाएगी। ऐसा नहीं कि इन विसंगतियों को पहले चिह्नित न किया गया हो। वर्ष 2006 से 2009 के बीच द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के माध्यम से केंद्र सरकार के स्तर पर 15 रिपोर्ट और 1,514 सिफारिशें प्रस्तुत की गई थीं। इनमें से सरकार ने 1,183 को स्वीकार भी कर लिया था। इनके क्रियान्वयन का अंतिम बार हिसाब मई 2012 में दिया गया था। तब यह संख्या 533 दर्ज की गई थी और उसके बाद कभी इनकी गिनती ही नहीं हुई।यह सही है कि दिसंबर 2023 तक 1,562 अप्रासंगिक हो चुके पुराने कानूनों को निरस्त किया गया। इसी क्रम में जन विश्वास अधिनियम, 2023 के जरिये 183 प्रविधानों को आपराधिक बंदिश से मुक्त किया गया। वर्ष 2017 के बजट से योजनागत और गैर-योजनागत व्यय का भेद समाप्त कर दिया गया। ये तमाम सुधार ऐसे हैं, जिनसे व्यवस्था के भीतरी तंत्र के विशेषाधिकारों पर जरा भी आंच नहीं आई। जबकि जिन सुधारों को दफन कर दिया गया, वे सत्ता प्रतिष्ठान की मानसिकता को पूरी तरह बेनकाब करते हैं। मंत्रालयों के एकीकरण या उन्हें सुगठित बनाने का यही अर्थ है कि नेताओं के विशेषाधिकारों पर चोट होना।सिविल सेवाओं के लिए एक कड़ा कानून भी अधिकारियों के सुरक्षा आवरण और सुविधावादी रवैये पर आघात करता है। असल में जब कुछ समूह अपने निहित स्वार्थों के लिए लामबंद होते हैं, तो सुधार वहीं दम तोड़ देते हैं। इस क्रम में विशेषाधिकार संपन्न वर्ग अपने मनमाने अधिकारों या विवेकाधिकारों की रक्षा में उतर आता है। भारत में सुधारों का क्रियान्वयन उनकी उपयोगिता या योग्यता से नहीं, बल्कि इस बात से निर्धारित हुआ है कि उनकी आंच किसको झेलनी पड़ेगी। स्पष्ट है कि यहां बीमारी पहचान करने में कोई समस्या नहीं, बल्कि वास्तविक समस्या उसके उपचार की है कि उसमें किसकी जवाबदेही तय की जाए।स्पष्ट है कि सुधारों की राह में परियोजनाओं की पूर्णता को लेकर अनुशासन बरतना होगा। सरकारों को मुकदमेबाजी के चलन से बचना होगा। परियोजनाओं की एक मियाद भी तय करनी होगी। प्रशासनिक अधिकारियों के कैडर का संतुलित रूप से पुनर्गठन करना होगा। हर विभाग का समग्रता में उचित मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाए। यदि हमें विकसित भारत के लक्ष्य की पूर्ति करनी है तो अगले दो दशकों तक करीब आठ प्रतिशत की दर से आर्थिक वृद्धि करनी होगी।कोई भी देश जर्जर प्रशासनिक मशीनरी के बूते ऐसा लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया है। विकसित भारत का आह्वान तो दिल्ली से हुआ था, लेकिन इसकी शुरुआत जयपुर से होती दिख रही है। प्रशासनिक सुधारों के मोर्चे पर दिल्ली को अब और देर नहीं करनी चाहिए।

बदलती विश्व व्यवस्था के बीच बढ़ते परमाणु खतरे

डॉ. अरुण मित्रा

पश्चिम एशिया में बढ़ता संघर्ष एक व्यापक युद्ध की संभावना को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बार-बार ईरान को धमकियां दी हैं, और कई बार तो उसे पूरी तरह नष्ट करने की बात भी कही है। यह देखना बाकी है कि क्या ये बयान केवल दबाव बनाने के लिए हैं या फिर किसी बड़ी सैन्य कार्रवाई की शुरुआत हैं। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मार्को रुबियो का बयान, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर ईरान को धमकी दी, अमेरिकी प्रशासन के अहंकार को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में दुनिया लापरवाह नहीं रह सकती। विभिन्न स्रोतों से मिल रही जानकारी के अनुसार, ईरान को अमेरिका और इजरायल की ओर से एक नए हमले की आशंका है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इजरायल परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करता है, तो ईरान इजरायल के परमाणु प्रतिष्ठानों को पूरी तरह नष्ट कर देगा, जो डिमोना शहर के दक्षिण-पूर्व में नेगेव रेगिस्तान में स्थित हैं। ब्राजीलियाई पत्रकार एमिलियो पेपे एस्कोबार ने ट्रांजिशन प्रोटोकॉल नामक डिजिटल चैनल पर जुल्फिकार अली के साथ एक साक्षात्कार में बताया कि ईरान ने लगभग 400 ठिकानों को चिह्नित कर लिया है, जिनमें खाड़ी क्षेत्र में स्थित अमेरिकी ठिकानों से लेकर हिंद महासागर तक के ठिकाने शामिल हैं। इस बीच, हेब्रोन के पास गोलीबारी की घटना के बाद इजरायल द्वारा वेस्ट बैंक में लॉकडाउन लगाने की खबरें और अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ की हालिया इजरायल यात्रा भी गौर करने लायक हैं। ईरान के प्रतिरोध ने अमेरिकी सैन्य शक्ति की सीमाओं को उजागर कर दिया है। होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही में रुकावट ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को बुरी तरह प्रभावित किया है और आर्थिक दबाव बढ़ा दिया है। डीजल सहित ईंधन की आपूर्ति में आ रही दिक्कतों ने वाशिंगटन की नीतियों के आर्थिक परिणामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कहा जाता है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वाशिंगटन को यह विश्वास दिलाया था कि ईरान कुछ ही दिनों में आत्मसमर्पण कर देगा। इसी वजह से अमेरिका, ईरान के खिलाफ इजरायल की आक्रामकता में शामिल हो गया। इससे संघर्ष और



तेज हो गया। अपनी सैन्य श्रेष्ठता के बावजूद, अमेरिका को वह निर्णायक परिणाम नहीं मिला, जिसकी उसे और इजरायल को उम्मीद थी। खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के हमलों से भारी नुकसान हुआ है। ट्रम्प द्वारा ईरान के साथ बनी राजनयिक समझ को खत्म कर देने से शांति की संभावनाएं और कमजोर हो गई हैं। हूती विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब पर किए गए हमलों ने बाबअल-मंदेब जलडमरूमध्य और लाल सागर से होने वाले समुद्री व्यापार को बाधित किया है, जिसका सऊदी अरब पर गंभीर असर पड़ा है। ब्रिक्स के उदय और चीन की बेल्ट एंड रोड पहल - जिसमें विभिन्न महाद्वीपों के लगभग 150 देश शामिल हैं- से विश्व व्यवस्था में बदलाव के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। अमेरिका और पूर्व औपनिवेशिक शक्तियां इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। अमेरिका, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों को दरकिनार करते हुए, अपनी मनमर्जी से विभिन्न देशों पर प्रतिबंध और शुल्क थोपकर दुनिया पर अपनी शर्तें थोपने की कोशिश कर रहा है। मौजूदा भारतीय सरकार, अमेरिका के साथ बहुत करीबी संबंध रखना चाहती है, भले ही अमेरिका अपनी शर्तें थोपता हो। डोनाल्ड ट्रम्प ने कई बार भारत को यह कहकर अपमानित किया है कि अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद ही भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुका था। वे उस श्विशेष मित्रता्य की कोई परवाह नहीं करते, जिसका अक्सर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिक्र करते हैं। इसी व्यापक भू-राजनीतिक संदर्भ में, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की भारत यात्रा महत्वपूर्ण हो जाती है। उनकी यात्रा की शुरुआत नई दिल्ली में औपचारिक बातचीत से होने के बजाय, मुंबई और जामनगर से हुई। इससे इस यात्रा के उद्देश्य और इसके आयोजन के तरीके पर सवाल खड़े हो गए हैं। रिपोर्टों के अनुसार, रुबियो की मेजबानी उद्योगपति मुकेश अंबानी ने की। साथ ही, इस यात्रा के बारे में जानकारी भारतीय सरकार की ओर से कोई सार्वजनिक घोषणा होने के बजाय, अमेरिकी पक्ष से सामने आई। इतने वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी की यात्रा का आयोजन राष्ट्रीय राजधानी से बाहर क्यों किया गया? क्या भारतीय सरकार की प्राथमिकताओं और राजनयिक प्रोटोकॉल का उचित सम्मान किया गया? ऐसे समय में जब भारत को बड़े विदेशी निवेश की जरूरत है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में निवेश और टेक्सास में एक संभावित प्लांट लगाने को लेकर हुई चर्चाओं की खबरों ने अटकलों को और बढ़ा दिया है। इन दावों की- कि अंबानी टेक्सास और वेनेजुएला में 300 अरब डॉलर का निवेश कर सकते हैं- स्वतंत्र पुष्टि और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। उतनी ही चिंताजनक यह खबर भी है कि अमेरिकी राजदूत सर्जियोगोर ने विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर से रुबियो से मिलने के लिए मुंबई जाने को कहा। यदि यह सच है, तो ये हालात राजनयिक प्रोटोकॉल और आपसी सम्मान को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। भारत-पाकिस्तान संघर्ष, व्यापार शुल्क और रूस से भारत द्वारा तेल खरीदने के मुद्दों पर राष्ट्रपति ट्रम्प के सार्वजनिक बयानों के बावजूद, मोदी सरकार वाशिंगटन के साथ अपने करीबी संबंध बनाए हुए है। भारत को अमेरिका की रणनीतिक प्राथमिकताओं को क्यों मानना चाहिए, जबकि अमेरिका हमेशा अपने हितों को ही सबसे ऊपर रखता है? अमेरिका के इस वर्चस्ववादी रवैये ने पूरी दुनिया को अस्थिरता की ओर धकेल दिया है और हर तरफ सैन्य तनाव बढ़ा दिया है। परमाणु टकराव का खतरा इस मौजूदा स्थिति को विशेष रूप से चिंताजनक बनाता है। ईरान ने बार-बार परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश से इन्कार किया है, जबकि अमेरिका और इजरायल उसके परमाणु कार्यक्रम को सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बताते रहे हैं। ऐसे दावों की जांच विश्वसनीय अंतरराष्ट्रीय सत्यापन और स्थापित अंतरराष्ट्रीय कानूनों के जरिए होनी चाहिए, न कि इनका इस्तेमाल एकतरफा सैन्य कार्रवाई के बहाने के रूप में किया जाना चाहिए। इराक युद्ध एक गंभीर सबक देता है। 2003 में अमेरिका के नेतृत्व में हुए हमले को सही ठहराने के लिए जनसंहार के हथियारों का हवाला दिया गया था, लेकिन जिन हथियारों के जखीरे का मुख्य आधार के रूप में जिक्र किया गया था, वे कभी मिले ही नहीं। इराक और पूरे क्षेत्र पर पड़े विनाशकारी परिणाम यह दिखाते हैं कि विवादित दावों के आधार पर युद्ध छेड़ने के कितने खतरे हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र को स्थिति को और बिगड़ने से रोकने और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अपने राजनयिक प्रयासों को तुरंत तेज करना चाहिए। उसे परमाणु हथियार संपन्न सभी देशों पर दबाव डालना चाहिए कि वे यह पक्का वादा करें कि वे चल रहे संघर्षों में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। परमाणु हथियारों का सीमित इस्तेमाल भी भारी जान-माल का नुकसान, पर्यावरण की तबाही, खाद्य असुरक्षा और स्वास्थ्य पर ऐसे दीर्घकालिक दुष्प्रभाव पैदा कर सकता है, जो इसमें शामिल देशों की सीमाओं से कहीं दूर तक फैल सकते हैं। एक बड़े पैमाने पर होने वाला परमाणु युद्ध तो पूरी मानव सभ्यता के अस्तित्व के लिए ही खतरा बन सकता है। नेतृत्व की असली परीक्षा किसी दूसरे देश को डराने-धमकाने की क्षमता में नहीं, बल्कि युद्ध को रोकने और मानवता की रक्षा करने के दृढ़संकल्प में होती है। भारत को यह तय करना होगा कि क्या वह स्वतंत्र रूप से नई विश्व व्यवस्था को आकार देने में मदद करेगा या फिर अपनी विदेश नीति को किसी वर्चस्ववादी शक्ति के हिसाब-किताब से तय होने देगा।

त्यौहार के समय जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतें परिवारों के बजट पर भारी

कल्याणी शंकर

त्यौहारी मौसम के दौरान आने वाली ये आर्थिक चुनौतियां उन छोटे व्यवसायों को प्रभावित कर सकती हैं, जो पूरी तरह से अपनी बिक्री पर निर्भर हैं। बढ़ती कीमतें मुनाफे के मार्जिन को कम कर सकती हैं, लेकिन ये हाथ से बनी वस्तुओं के महत्व को भी उजागर करती हैं। अनोखे और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद पेश करके, स्थानीय विक्रेता उन ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हैं जो असली और पारंपरिक चीजों की तलाश में हैं। भारत में त्यौहार एक महत्वपूर्ण परम्परा है, सिर्फ जश्न मनाने का मौका नहीं। इसलिए इस दौरान परिवार नए कपड़े, मिठाइयां, सजावट के सामान और उपहार खरीदने पर काफी पैसा खर्च करते हैं। हालांकि, बढ़ती कीमतें और महंगाई उपभोक्ताओं को अपना बजट और खरीदारी के तरीके बदलने पर मजबूर कर रही हैं। कई परिवार अब त्यौहारों को छोटे स्तर पर मना रहे हैं और सस्ती चीजें तलाश रहे हैं। मौसम के अनिश्चित मिजाज के कारण प्याज, लहसुन और अदरक जैसी जरूरी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में भारी उछाल आया है। इसके अलावा, वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और भारतीय रुपया कमजोर हो रहा है। इससे परिवहन और खनिज तेल की लागत बढ़ गई है। थोक बाजार में खनिज तेल की कीमतें पिछले साल के मुकाबले करीब 40 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं। कोर महंगाई दर बढ़कर 4.6 प्रतिशत हो गई है, जिसका असर खाने-पीने की चीजों, ईंधन, सेवाओं और अन्य सामानों की कीमतों पर पड़ रहा है। महंगाई को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए सिर्फ मौद्रिक नीति काफी नहीं है। इसके लिए समन्वित राजकोषीय उपायों की भी जरूरत है। इसमें नकदी प्रवाह का प्रबंधन, करों में बदलाव, और कृषि तथा आपूर्ति श्रृंखला में सुधार जैसे कदम शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति ने रेपोरेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी करके इसे 5.50 प्रतिशत कर दिया है। लगभग चार वर्षों में यह पहली बार है जब दरों में बढ़ोतरी की गई है। नीतिगत रुख को कड़ा से बदल कर नरपेक्ष करने का मतलब है कि निकट भविष्य में दरों में कटौती की संभावना कम है। मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष और कमजोर मानसून के कारण खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ी हैं, जिससे महंगाई को लेकर चिंताएं और गहरी हो गई हैं। नतीजतन, अगले एक साल में दरों में 100 बेसिस पॉइंट्स से ज्यादा की और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। सितंबर में थोक महंगाई दर अगस्त के 9.92 प्रतिशत से बढ़कर 11.39प्रतिशत हो गई, जिसका मुख्य कारण तेल की कीमतों में 57.32 प्रतिशत की भारी वृद्धि थी। आरबीआई प्रमुख संजय मल्होत्रा ने कहा कि भविष्य में दरों में बढ़ोतरी आर्थिक विकास और महंगाई के रुझानों पर निर्भर करेगी। अब बड़ा सवाल यह है कि सितंबर में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा स्वीकार की गई कीमतों में बढ़ोतरी का, उपभोक्ताओं के लिए कीमतों और बिजली के बिलों पर कितना असर पड़ेगा?त्यौहारी मौसम के दौरान आने वाली ये आर्थिक चुनौतियां उन छोटे व्यवसायों को प्रभावित कर सकती हैं, जो पूरी तरह से अपनी बिक्री पर निर्भर हैं। बढ़ती कीमतें मुनाफे के मार्जिन को कम कर सकती हैं, लेकिन ये हाथ से बनी वस्तुओं के महत्व को भी उजागर करती हैं। अनोखे और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद पेश करके, स्थानीय विक्रेता उन ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हैं जो असली और पारंपरिक चीजों की तलाश में हैं। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की समस्याओं और घरेलू नीतियों ने भारत में महंगाई पर काफी असर डाला है। सितंबर 2023 में, भारतीय रिजर्व बैंक ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर 6.2 प्रतिशत बताई, जो इसके 2-6प्रतिशत के लक्ष्य दायरे से अधिक है। यह वृद्धि मुख्य रूप से भोजन, ईंधन और आवश्यक वस्तुओं की ऊंची कीमतों के कारण हुई है, जिसमें खाद्य महंगाई दर लगभग 7.8 प्रतिशत रही है।हाल ही में उठाए गए कदमों में खाना पकाने की गैस और अनाज जैसी आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स में कटौती और सब्सिडी देना शामिल है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने त्यौहारी मौसम से पहले आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने और महंगाई को कम करने के लिए खरीद के प्रयासों को तेज कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2026-27 के लिए 7.1 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर का अनुमान लगाया है, जिसमें खुदरा महंगाई दर 5.2 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। हालांकि, साल की आखिरी तिमाही (अक्टूबर से दिसंबर) में महंगाई बढ़कर 6 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। आरबीआई प्रमुख ने जोर देकर कहा कि भले ही अर्थव्यवस्था मजबूत है, लेकिन बढ़ती महंगाई अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। खुदरा विक्रेता इन आर्थिक रुझानों के अनुसार खुद को ढाल रहे हैं। वे आवश्यक वस्तुओं पर बंडल डील और छूट देकर ग्राहकों को पैसे की सही कीमत देने पर जोर दे रहे हैं। इस रणनीति से मध्यम श्रेणी के उत्पादों की बिक्री में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि विलासितापूर्ण वस्तुओं की मांग में कमी आई है। स्थानीय बाजार और कारीगर इन आर्थिक चुनौतियों के बीच खुद को ढाल रहे हैं। उनके लिए त्यौहार का समय उनकी सालाना कमाई का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा होता है। इंस्टाग्राम और पिनटेरेस्ट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे सुझावों से भरे पड़े हैं, जो इस दौरान लोगों को रचनात्मकता और संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सरकार ने खाना पकाने की गैस और अनाज जैसी जरूरी चीजों पर टैक्स में कटौती और सब्सिडी लागू की है। भारतीय खाद्य निगम ने भी आपूर्ति को लगातार बनाए रखने के लिए खरीद के प्रयासों को बढ़ाया है। इन उपायों का उद्देश्य त्यौहारी मौसम के करीब आते ही महंगाई को नियंत्रित करना है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने ग्राहकों को कीमतों के रुझानों के बारे में जागरूक करने और खरीदारी के लिए दिशा-निर्देश देने के लिए अभियान शुरू किए हैं, ताकि आर्थिक चुनौतियां त्यौहारों की खुशियों पर भारी न पड़ें। शिपिंग में रुकावटों, उर्वरकों की ऊंची लागत और श्अलनीनोश् के प्रभावों के कारण 2027 तक वैश्विक खाद्य महंगाई बढ़ने की आशंका है। इंडोनेशियाई चावल और भारतीय चीनी की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं, और मिस्र में ब्रेड की कीमतों में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। स्टॉक में कमी और आयात बढ़ने के कारण कीमतों में और उछाल आने का अनुमान है। अपनी ताजा रिपोर्ट में, आरबीआई ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच महंगाई दर में अंतर को रेखांकित किया है, जिसमें ग्रामीण इलाकों में महंगाई अधिक देखी गई है। इन समस्याओं से निपटने के लिए, सब्जियों जैसी जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के भंडारण, प्रसंस्करण और वितरण के बुनियादी ढांचे में सुधार करना जरूरी है। इसके अलावा, घरेलू स्तर पर तिलहन का उत्पादन बढ़ाकर खाद्य तेल के आयात पर निर्भरता कम करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि, लॉजिस्टिक्स और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में मौजूद बाधाओं को दूर करना आवश्यक है। औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने से अनौपचारिक क्षेत्र में कीमतों के उतार-चढ़ाव को कम करने में भी मदद मिल सकती है। इन चुनौतियों के बावजूद, त्यौहारों के मौसम में उपभोक्ता और व्यवसाय लगातार लचीलापन और रचनात्मकता दिखा रहे हैं।

अलीगंज सर्राफा व्यापारी लूटकांड : दीपक, गोलू पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित

शिवम सोलंकी

एटा। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में 22 अक्टूबर को थाना अलीगंज क्षेत्र में एक सर्राफा व्यापारी के साथ नीली अपाचे बाइक सवार तीन बदमाशों द्वारा चांदी और सोने के जेवरात से भरा एक बैग तमंचा और पिस्टल दिखाकर छीन लिया गया था। सर्राफ से हुयी लूट की घटना के कारण अलीगंज क्षेत्र के व्यापारियों एवं आमजन में डर एवं भय का माहौल व्याप्त था। उच्चाधिकारियों द्वारा 6 टीमों का गठन घटना के अनावरण हेतु किया गया था। गठित टीमों द्वारा कस्बा अलीगंज तथा घटनास्थल के आसपास लगे सैकड़ों सीसीटीवी का अवलोकन किया गया तो उसमें नीली अपाचे बाइक सवार 3 व्यक्ति पीड़ित की दुकान के पास रुकते हुए तथा पैदल ही दुकान की रैकी करते हुए दिखाई देते हैं। सीसीटीवी में देखने से एक बदमाश की पहचान होती है जिसका नाम वीरेंद्र पुत्र गुमान सिंह निवासी मैनपुरी था जो 17 अक्टूबर को जेल से रिहा हुआ था । टीमों द्वारा पीड़ित की दुकान की तरफ आने वाले मार्गों तथा घटना करने के उपरांत बदमाशों के भागने के मार्गों पर लगे करीब 2000 सीसीटीवी कैमरों का विश्लेषण करने के उपरान्त यह पाया जाता है कि तीनों बदमाश मैनपुरी क्षेत्र से आते हुए तथा घटना करने के बाद भागते समय कासगंज क्षेत्र होते हुए वापस मैनपुरी की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तत्समय पहचान में आए बदमाश वीरेंद्र पुत्र गुमान सिंह के संबंध में जानकारी करने पर उसके विरुद्ध कुल 53 गम्भीर अभियोग जैसे हत्या, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर, लूट, डकैती और रंगदारी इत्यादि का होना पाया गया। पहचान प्रमाणित होने पर अभियुक्त के ऊपर 1,00,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। अभियुक्त वीरेन्द्र द्वारा घटना के दौरान जो कपड़ा पहना गया था उस कपड़े के आधार सीसीटीवी देखते हुए पुलिस टीम द्वारा 22 अक्टूबर को वीरेंद्र को मैनपुरी जिला कचहरी में भी घटना के पूर्व उसी कपड़े को पहना हुआ पाया गया तथा वहां गोपनीय सूत्र से भी वीरेन्द्र की पहचान सुनिश्चित की गई। वीरेंद्र के साथ बाइक सवार शेष बदमाशों के रुप में दीपक गिरि उर्फ अखिलेश गिरी निवासी थाना रानीगंज जनपद मऊ तथा गोलू उर्फ कुलदीप पंडित निवासी थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद को भी सीसीटीवी कैमरों, अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों तथा घटना की साजिश रचने वाले गिरफ्तार हो चुके अभियुक्तों गौरव चौहान व मंगलम मिश्रा से हुई पूछताछ से प्रमाणित किया गया जिसके आधार पर वांछित अभियुक्त दीपक गिरि व गोलू पंडित पर 25,000-25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। जिसमें अभियुक्त दीपक गिरि के विरुद्ध 22 मुकदमे तथा अभियुक्त गोलू उर्फ कुलदीप पंडित के विरुद्ध 4 मुकदमें दर्ज है । गठित टीमों द्वारा शीघ्र ही इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।



दिल्ली में 'वोट बचाओ महारैली' में शामिल होंगे एटा के 500 लोग : सत्याबहन

भूपेन्द्र सोनी

एटा। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, पूर्व सदस्य कांग्रेस वर्किंग कमेटी तथा पूर्व सदस्य अनुसूचित जाति आयोग (भारत सरकार) सत्याबहन ने आज यहाँ एक प्रेसवार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने 1 नवंबर को दिल्ली में आयोजित होने वाली 'वोट बचाओ महारैली' की तैयारियों और रूपरेखा पर विस्तार से जानकारी दी। सत्याबहन ने बताया कि यह महारैली लोकतंत्र की रक्षा और मतदाताओं के अधिकारों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि देशभर से कांग्रेस कार्यकर्ता और आम नागरिक इस रैली में शामिल होंगे। रैली की तैयारियों को लेकर पार्टी ने व्यापक स्तर पर संपर्क अभियान शुरू किया है। प्रेस वार्ता में उन्होंने विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के एटा जिले का उल्लेख करते हुए कहा कि एटा की चारों विधानसभा क्षेत्रों से लगभग 500 लोग 'वोट बचाओ महारैली' में पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि इनमें पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता, स्थानीय नेता और आम समर्थक शामिल हैं, जो निजी वाहन, रेल, बसों और अन्य वाहनों से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। एटा से भागीदारी को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। प्रेसवार्ता के दौरान पार्टी के अन्य स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। सत्याबहन ने सभी से 1 नवंबर की रैली को ऐतिहासिक बनाने की अपील की है। इस अवसर पर अजय कुमार एडवोकेट ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। ठाकुर अनिल सोलंकी (पीसीसी), रामकुमार सक्सेना (पीसीसी) तथा विनीत परासर बाल्मीकि (शहर अध्यक्ष) ने कांग्रेसियों को तिरंगा, पटका पहनाकर स्वागत किया। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व ब्लॉक प्रमुख डॉ0 गीतम सिंह, दिनेश यादव (प्रदेश महासचिव, पिछड़ा वर्ग कांग्रेस), संजीव गुप्ता (जिलाध्यक्ष, सेवा दल), सुनील गौतम (जिलाध्यक्ष, किसान कांग्रेस), सुभाष सागर एडवोकेट (पूर्व सभासद), सुशील चंद्र शर्मा (जिला उपाध्यक्ष, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन), पंकज गौतम (शहर अध्यक्ष, अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस), रामरत्न बाल्मीकि (पूर्व जिला महासचिव), सोमबीर सिंह दिवाकर, संदीप यादव (जिला उपाध्यक्ष, युवा कांग्रेस), शिवा चौधरी, संदीप बाल्मीकि, दिनेश चंद्र सागर, उदय सागर, मधुर कांत कश्यप, मयंक यादव आदि उपस्थित रहे।

आमिर खान पर हमला करना चाहते थे शूटर्स, लेकिन टाइगर श्रॉफ पर चली गोलियां, फायरिंग केस में सामने आया नया खुलासा



बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफकी गाड़ी पर कुछ हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थीं। इस घटना में टाइगर बाल-बाल बच गए। मामले की जांच के दौरान पुलिस अब तक कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं, इस केस में एक नया और चौंकाने वाला एंगल सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, टाइगर श्रॉफ से पहले हमलावरों ने अभिनेता आमिर खान के घर की रेकी की थी। दावा किया जा रहा है कि इस पूरे मामले में आमिर खान पहले निशाने पर थे। आखिर हमलावरों ने टाइगर श्रॉफको कैसे टारगेट किया और इस मामले में आमिर खान का नाम कैसे सामने आया ? आइए जानते हैं पूरे मामले की जानकारी। एक रिपोर्ट के अनुसार, टाइगर श्रॉफफायरिंग मामले की जांच में पुलिस को पूछताछ के दौरान कुछ अहम जानकारियां मिली हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि टाइगर श्रॉफहमलवारों के शुरुआती निशाने पर नहीं थे बल्कि इससे पहले उन्होंने अभिनेता आमिर खान को टारगेट करने की योजना बनाई थी। हालांकि, इस दावे की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। इसके अलावा हमलावरों ने आमिर ने आमिर खान के मुंबई स्थित घर की कथित तौर पर तीन बार रेकी की थी। इस दौरान उन्होंने अभिनेता की गतिविधियों पर नजर रखने और उनके आने-जाने के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की। हालांकि, हमला करने का अनुकूल मौका नहीं मिल पाने के कारण वे कथित तौर पर अपनी योजना को अंजाम नहीं दे सके। जांच में सामने आई जानकारी के मुताबिक, आमिर खान पर हमला करने की कथित योजना नाकाम रहने के बाद हमलावरों ने टाइगर श्रॉफको निशाना बनाने का प्लान बनाया। बताया जा रहा है कि टाइगर जुहू स्थित एक पार्क में फुटबॉल खेलने के लिए आते थे। हमलावरों ने इसी बात का फायदा उठाया और मौका मिलने पर उनकी कार पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। हालांकि, इस मामले में टाइगर श्रॉफबाल-बाल बच गए। इससे पहले भी टाइगर श्रॉफफायरिंग मामले की जांच के दौरान कुछ अन्य बॉलीवुड सितारों के नाम संभावित निशाने के तौर पर सामने आने की खबरें आई थीं। इनमें रणबीर कपूर, सलमान खान और अक्षय कुमार के नाम भी शामिल बताए गए थे। हालांकि, इन दावों की आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है।

›››› बॉलीवुड ‹‹‹‹

अनुष्का शर्मा फिर सुर्खियों का हिस्सा

वायरल वीडियो पर फैंस पूछने लगे – क्या आने वाला है तीसरा मेहमान?

पति विराट कोहली के साथ गेटवे ऑफइंडिया पर नजर आईं अनुष्का शर्मा का नया वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी तीसरी प्रेग्नेंसी की अटकलें शुरू हो गई हैं। वीडियो में अनारकली सूट पहने अनुष्का को देखकर यूजर्स तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं। हालांकि, इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा अपनी एक्टिंग और अलग अंदाज से लोगों के बीच खास पहचान बना चुकी हैं। अनुष्का भले ही लंबे समय से फिल्मों से दूर हैं, लेकिन वह अक्सर किसी न किसी वजह से चर्चा में रहती हैं। हाल ही में वह पति विराट कोहली के साथ अमेरिकी भक्ति गायक कृष्ण दास के कीर्तन में नजर आई थीं। इस दौरान दोनों भक्ति में लीन दिखाई दिए थे। अब अनुष्का का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद उनकी प्रेग्नेंसी को लेकर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं।

वायरल वीडियो के बाद अनुष्का की प्रेग्नेंसी पर सवाल

अनुष्का शर्मा और विराट कोहली हाल ही में गेटवे ऑफइंडिया के पास नजर आए। इस दौरान अनुष्का ने अनारकली सूट पहना हुआ था। वीडियो सामने आने के बाद कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके कपड़ों और लुक को देखकर उनकी तीसरी प्रेग्नेंसी को लेकर अटकलें लगानी शुरू कर दीं। एक यूजर ने लिखा, ष्लगता है तीसरा मेहमान जल्द आने वाला है ष् वहीं दूसरे यूजर ने सवाल किया, ष्क्या ये प्रेग्नेंट हैं?ष् एक अन्य यूजर ने लिखा, लगता है विराट और अनुष्का तीसरी बार मम्मी-पापा बनने वाले हैं। हालांकि, अनुष्का शर्मा की तीसरी प्रेग्नेंसी की खबर फिलहाल सिर्फसोशल मीडिया पर चल रही अटकलों तक सीमित है। इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।





यशराज फिल्म्स की नई पेशकश 'बेपरवाह', पहली बार साथ नजर आएंगे अहान पांडे और शरवरी

यशराज फिल्म्स ने अपनी आगामी रोमांटिक एक्शन-ड्रामा फिल्म 'बेपरवाह' के टाइटल की घोषणा कर दी है। अली अब्बास जफर के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में अहान पांडे और शरवरी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण आदित्य चोपड़ा कर रहे हैं। मेकर्स ने फिल्म के टाइटल के साथ इसका टीजर पोस्टर भी जारी किया है। सिनेमाघरों में रिलीज होने से पांच महीने पहले किए गए इस ऐलान ने फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा दी है। 'सैयारा' से लोकप्रियता हासिल करने वाले अहान पांडे और शरवरी पहली बार इस फिल्म के जरिए बड़े पर्दे पर एक साथ दिखाई देंगे। निर्देशक अली अब्बास जफर एक बार फिर यशराज फिल्म्स के साथ काम कर रहे हैं। इससे पहले वह इस प्रतिष्ठित प्रोडक्शन हाउस के लिए 'जैसी सफल फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। अब 'बेपरवाह' के जरिए वह एक नई रोमांटिक एक्शन-ड्रामा कहानी लेकर आ रहे हैं। फिल्म के टाइटल और टीजर पोस्टर की घोषणा के साथ ही दर्शकों को अहान पांडे और शरवरी की नई ऑनस्क्रीन जोड़ी



देखने का इंतजार है। रोमांस और एक्शन के मेल से सजी इस फिल्म में दोनों कलाकारों की केमिस्ट्री कहानी का अहम हिस्सा होने की उम्मीद है। आदित्य चोपड़ा के निर्माण और अली अब्बास जफर के निर्देशन में बन रही 'बेपरवाह' 26 मार्च 2027 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

›››› बॉलीवुड ‹‹‹‹

भगवान राम का किरदार निभाकर बदले रणबीर कपूर, कहा, ये रोल निभाने के बाद उन्हें राहा के लिए बेहतर पिता बनने में मदद मिली



बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर ने बताया कि आने वाली महाकाव्य फिल्म श्रामायण में भगवान राम का किरदार निभाना सिर्फएक रोल नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अभिनेता ने यह भी स्वीकार किया कि जब उन्हें यह रोल ऑफर हुआ, तो सबसे पहले उनके मन में डर और खुद पर संदेह पैदा हुआ। अभिनेता ने मेगास्टार अमिताभ बच्चन द्वारा होस्ट किए जाने वाले लोकप्रिय क्विज रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति के दिवाली स्पेशल एपिसोड में इस खास किरदार की तैयारी के अपने सफर के बारे में बात की। इस अहम रोल के मिलने और अपनी शुरुआती घबराहट के बारे में बताते हुए, रणबीर कपूर ने होस्ट अमिताभ बच्चन से कहा, सर, जब मुझे यह रोल ऑफर हुआ, तो मैं जानता था कि यह सिर्फएक रोल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मेरे मन में सबसे पहले डर आया क्या मैं इसके काबिल हूं ? क्या मैं यह कर पाऊंगा ? क्योंकि करोड़ों लोगों की आस्था प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई है... उन्होंने बताया कि कैसे उनकी शुरुआती घबराहट बाद में गहरी कृतज्ञता में बदल गई।

उन्होंने आगे कहा, पर बहुत जल्दी सर ये, ये जो डर था वो आभार में बदला, कि मुझे इस मुकाम में, मेरी जिंदगी की इस उम्र में, मुझे ये मौका मिल रहा है, एक अच्छा एक्टर बनने का। एक्टर सर को भूल जाइए, एक अच्छा इंसान बनने का मौका, उसी दौरन सर, मैं पहली बार पिता बना। मेरी बेटी राहा का जन्म हुआ, तो मैं यही मानता हूं कि यह भगवान का उपहार था सर, मुझे एक बेहतर इंसान बनने का मौका मिला, गहरी से रामायण को समझने का मौका मिला, इन सब लोगों के साथ, खूबसूरत लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। महाकाव्य के मूल्यों को आत्मसात करने पर अपने हार्दिक विचारों को समाप्त करते हुए, रणबीर ने कहा, सर हम। प्रभु श्री राम के जैसा बनना तो संभव नहीं है, लेकिन उनके आदर्शों से कुछ सीखना मेरे ख्याल से हम सभी के लिए बहुत बड़ी बात है।

अपने साउथ इंडियन एक्सेंट पर ट्रोल हुई रश्मिका मंदाना, सपोर्ट में उतरीं एक्ट्रेस मधु, कही दिल छूने वाली बात

हाल ही में कॉफी विद करण शो के एक एपिसोड में रश्मिका मंदाना ने अपने दक्षिण भारतीय लहजे के बारे में बात की थी, जिसके बाद अभिनेत्री मधु उनके समर्थन में सामने आई हैं। मधु ने रश्मिका की इस बात के लिए तारीफकी कि उन्होंने अपनी पहचान को अपनाया और आलोचनाओं का सामना पूरे आत्मविश्वास के साथ किया। सोशल मीडिया पर अपनी आई एम इन लव सीरीज के तहत शेयर किए गए एक वीडियो में, मधु ने बताया कि उन्होंने फिल्म निर्माता करण जौहर के टॉक शो कॉफी विद करण में रश्मिका को देखा और जिस तरह से उन्होंने अपने लहजे को लेकर हुई आलोचनाओं का जवाब दिया, उसकी काफी सराहना की। मधु ने कहा, मैंने हाल ही में रश्मिका मंदाना का कॉफी विद करण शो देखा। अपने लहजे को लेकर हुई आलोचनाओं को उन्होंने जिस तरह से संभाला, वह मुझे बहुत अच्छा लगा। वह इस पर हंसती हैं, इसे स्वीकार करती हैं और गर्व से कहती हैं कि वह दक्षिण भारतीय हैं। वह कहती हैं, श्हां, मैं दक्षिण भारतीय हूं और मेरा लहजा भी दक्षिण भारतीय है। वह इसे लेकर बहुत सहज हैं और मुझे उनका यह अंदाज बहुत पसंद आया। उन्होंने आगे कहा, ष्कई साल पहले, जब मैं हिंदी फिल्मों में अभिनेत्री बनी थी, तो मुझे इस बात का बहुत डर था कि दक्षिण भारतीय होने की वजह से लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे। मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की। मैंने उर्दू सीखने के लिए एक टीचर रखा और अपनी हिंदी को बेहतर बनाया। मैंने हर मुमकिन कोशिश की ताकि मेरे लहजे की वजह से कोई मुझे पकड़ न सके या मुझ पर सवाल न उठाए। मधु ने कहा,अगर कोई मेरी बोली में थोड़ा सा भी लहजा पकड़ लेता, तो मैं बहुत परेशान हो जाती और उसे सुधारने के लिए और ज्यादा मेहनत करती। मुझे बहुत गर्व महसूस होता था जब लोग कहते थे कि मेरी हिंदी, हिंदी बोलने वालों से भी बेहतर है। यह मेरा सफर था। आज, मुझे यह कहते हुए बहुत गर्व होता है कि मैं एक दक्षिण भारतीय हूं। अगर मुझसे हिंदी बोलने में कोई गलती हो जाती है या मेरी बोली में दक्षिण भारतीय लहजा आ जाता है, तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां तक पहुंचने में मुझे 30 से 35 साल लग गए। उन्होंने आगे कहा, रश्मिका, तुम बहुत मजबूत हो! मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम इसे अपनाती हो, इस पर हंसती होकृतुम सच में एक स्टार हो ।वीडियो के साथ अभिनेत्री ने कैप्शन में लिखा, मुझे दक्षिण भारतीय होने और अपने दक्षिण भारतीय लहजे पर गर्व है। मुझे यहां तक पहुंचने में 30 साल लग गए, लेकिन रश्मिका, तुम पहले ही उस मुकाम पर हो। हाल ही में तुम्हारा एक इंटरव्यू देखा, जिसमें तुम्हारी यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तुम बहुत मजबूत हो, बस ऐसी ही स्टार बनी रहो... अभिनेत्री की यह टिप्पणी तब आई है, जब हिंदी



उच्चारण को लेकर हो रही आलोचनाओं के बीच जाने-माने गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर ने रश्मिका का समर्थन किया है। एक्स (पहले ट्विटर) पर जावेद अख्तर ने लिखा, जिन्हें तमिल अभिनेत्री रश्मिका के उच्चारण से कोई दिक्कत है, उन्हें तमिल भाषा की कुछ पंक्तियां पढ़ने के लिए दी जानी चाहिए। तमिल दुनिया की सबसे पुरानी बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है, देखते हैं कि वे इसे कितनी अच्छी तरह बोल पाते हैं। भाषा को लेकर यह बनावटी और बेबुनियाद श्रेष्ठता की भावना बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है।

भारत-कनाडा प्रवासन वार्ता : भारतीय प्रवासियों के हितों और सुरक्षा पर विशेष जोर

(एजेंसी)

नई दिल्ली। भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय संबंधों को एक नई दिशा देते हुए नई दिल्ली में श्भारत-कनाडा प्रवासन और गतिशीलता संवादश् की पहली ऐतिहासिक बैठक आयोजित हुई। इस उच्च स्तरीय बैठक की सह-अध्यक्षता भारतीय विदेश मंत्रालय की सचिव (सीपीवी एवं ओआईए) श्रीप्रिया रंगनाथन और कनाडा के आव्रजन, शरणार्थी और नागरिकता विभाग के उप मंत्री टेड गैलिवन ने की। इस दौरान दोनों पक्षों ने भविष्य के प्रवासन ढांचे को मजबूत करने के लिए आधिकारिक तौर पर



कार्य-शर्तों पर हस्ताक्षर किए। इस संवाद का मुख्य केंद्र बिंदु दोनों देशों के बीच सुरक्षित, व्यवस्थित और कानूनी आवाजाही को बढ़ावा देना रहा। बैठक में प्रवासन प्रबंधन और आवाजाही के रास्तों को अधिक सरल व पारदर्शी बनाने पर गहन चर्चा हुई। इस पहल का सबसे बड़ा लाभ कनाडा जाने वाले भारतीय छात्रों, कुशल पेशेवरों और कामगारों को मिलेगा। प्रवासन प्रक्रियाओं के आसान होने से वीजा आवेदन, वर्क परमिट और निवास संबंधी जटिलताएं कम होंगी, जिससे वहां रहने वाले विशाल भारतीय समुदाय (प्रवासियों) के हितों की बेहतर सुरक्षा हो सकेगी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा दोनों पक्षों ने इस बात को दोहराया कि भारत और कनाडा के बीच लोग ही सबसे मजबूत पुल हैं।

भारत के युवा और कुशल कार्यबल तथा कनाडा की जनसांख्यिकीय और श्रम बाजार की स्थितियों के बीच एक स्वाभाविक तालमेल है, जिसके कारण सुव्यवस्थित आवाजाही आज के समय की जरूरत बन गई है। यह संवाद हर साल आयोजित किया जाएगा और इसमें श्प्रवासन और गतिशीलता पर संयुक्त कार्य समूहश् सहयोग प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 'एक्स' पर लिखा दोनों पक्षों ने आवाजाही और प्रवासन प्रबंधन के लिए रास्ते आसान बनाने पर चर्चा की, जो भविष्य में भारत-कनाडा संबंधों के विकास में एक महत्वपूर्ण कारक साबित हो सकते हैं।

जॉर्डन ने गिरजाघर पर हुए हमले का दिया जवाब, सीरिया में सशस्त्र समहों पर किए हवाई हमले

(एजेंसी)

अम्मान। जॉर्डन की वायुसेना ने कराक शहर स्थित एक श्ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च पर शुक्रवार को हुए हमले के जवाब में सीरिया में सशस्त्र समूहों पर सोमवार शाम हवाई हमले किए। जॉर्डन की वायुसेना ने एक बयान में यह जानकारी दी। गिरजाघर पर हुए हमले में कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई थी। जॉर्डन की वायुसेना ने कहा कि इस कार्रवाई में इन आतंकवादी समूहों के कई सदस्य मारे गए एवं घायल हुए और उनके कई वाहन नष्ट हो गए। हालांकि, इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया कि ये कौन से समूह थे या हमले किस स्थान पर किए गए। इस सैन्य कार्रवाई से सीरिया में भारी आक्रोश उत्पन्न हो गया है। सीरिया के अधिकारियों का कहना है कि जॉर्डन की इस कार्रवाई में कई आम नागरिकों की मौत हुई है और इसे देश के प्राधिकारियों को सूचित किए बिना अंजाम दिया गया। सीरिया की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि उसने दक्षिणी दरा और सुवैदा प्रांतों में हुए हमलों में मारे गए सात लोगों के शव बरामद किए हैं। उसने कहा कि दरा प्रांत के ग्रामीण इलाके में एक तंबू पर हुए हमले में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई, जिनमें तीन बच्चे और एक महिला शामिल हैं, जबकि परिवार के तीन अन्य लोग घायल हो गए। एजेंसी के अनुसार, दो अलग-अलग हमलों में 80 वर्षीय और 60 वर्षीय दो बुजुर्गों की भी जान चली गई। सीरिया की सरकार ने कहा कि जॉर्डन की यह कार्रवाई श्बिना किसी पूर्व समन्वय या सूचना केश् की गई। उसने कहा कि सीरियाई प्राधिकारी घटना की परिस्थितियों की जांच कर रहे हैं और स्थिति पर चर्चा के लिए जॉर्डन के साथ बातचीत के रास्ते खुले हैं। बाद में सीरिया के बंदरगाह एवं सीमा शुल्क सामान्य प्राधिकरण ने जॉर्डन के साथ सीरिया की मुख्य सीमा चौकी को बंद करने की घोषणा की। इससे पहले, जॉर्डन के अधिकारियों ने पिछले सप्ताह हुए हमले के सिलसिले में सोमवार को तीन लोगों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने बताया कि यह गिरफ्तारी तड़के हुई मुठभेड़ के बाद हुई और तीनों आरोपी घायल हो गए। जॉर्डन की राजधानी अम्मान से लगभग 90 किलोमीटर दक्षिण में स्थित कराक शहर में एक अंतिम संस्कार के दौरान शुक्रवार को ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च पर हमला हुआ। कराक में अल्पसंख्यक ईसाई आबादी रहती है।

राजनीतिक स्वार्थ साधने का साधन नहीं, जिम्मेदारी है वीटो: भारत

(एजेंसी)

न्यूयॉर्क। भारत ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक बार फिर वैश्विक व्यवस्था में सुधार को लेकर बेहद कड़ा और स्पष्ट रुख अपनाया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) की पूर्ण बैठक (प्लेनरी) में वीटो के इस्तेमाल पर बोलते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी. हरीश ने सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों (पी5) को उनकी सीमाओं और जिम्मेदारियों का अहसास कराया। उन्होंने दोटूक शब्दों में कहा कि वीटो एक अत्यंत गंभीर जिम्मेदारी है, न कि संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ साधने का कोई साधन। राजदूत हरीश ने अपने संबोधन से जुड़ी एक वीडियो क्लिप 'एक्स' पर साझा की, जिसमें उन्होंने कहा सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से दो देशों ने पिछले साढ़े तीन दशकों से अधिक समय से एक



बार भी वीटो का इस्तेमाल नहीं किया है। इसके विपरीत, अंतरराष्ट्रीय शांति के निर्णयों को प्रभावित करने वाले अधिकांश वीटो या वीटो का उपयोग करने की धमकियां पी5 के अन्य तीन देशों की ओर से ही आती रही हैं। भारत ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में आम सहमति के अलिखित नियम अक्सर एक श्छिपे हुए वीटोश् के रूप में काम करते हैं, जो प्रतिबंध समितियों और महत्वपूर्ण निर्णयों को बाधित करते हैं। भारतीय राजदूत ने साफ किया कि वैश्विक सुरक्षा ढांचे में व्यापक बदलाव के बिना कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में श्ठुकड़ों में किए गए सुधारश् किसी काम नहीं आएंगे। इसके बजाय, सुधारों से जुड़े सभी पांचों प्रमुख पहलुओं, जिसमें सदस्यता की श्रेणियां, वीटो का प्रश्न, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, विस्तारित परिषद का आकार और कार्यप्रणाली शामिल हैं, पर एक साथ मिलकर व्यापक रूप से काम करने की सख्त जरूरत है। यह वक्तव्य सुरक्षा परिषद में अपनी स्थायी और उचित भूमिका के लिए भारत के लंबे समय से जारी प्रयासों की पुष्टि करता है। भारत सुरक्षा परिषद में सुधार लाने के लिए वर्षों से वैश्विक स्तर पर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भारत का हमेशा से यह स्पष्ट और सैद्धांतिक स्टैंड रहा है कि एक संशोधित और विस्तारित सुरक्षा परिषद में विकासशील देशों और श्ग्लोबल साउथश् को न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। भारत ने बिना वीटो अधिकार के नए सदस्यों को जोड़ने के विचार का हमेशा कड़ा विरोध किया है, क्योंकि इससे श्दूसरे दर्जेश् की सदस्यता का निर्माण होगा, जो आज की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं से मेल नहीं खाती। अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था, विशाल आबादी और शांति अभियानों में ऐतिहासिक योगदान के दम पर भारत, जी4 समूह (भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान) तथा अफ्रीकी देशों के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र में पूर्ण और समान अधिकारों वाली स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए निरंतर और अथक प्रयास कर रहा है।

अहम नेसेट चुनावों के लिए मतदान जारी : इजरायल

(एजेंसी)

यरूशलम। तेल अवीव नेसेट सदस्यों को चुनने के लिए इजरायल में वोटिंग जारी है। इस चुनाव में लगभग 73 लाख (7.3 मिलियन) लोग मतदान करने के पात्र हैं। मंगलवार को राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग, बेन ग्विर समेत कई हस्तियों ने अपने मतों का प्रयोग किया। चुनाव से ठीक पहले आए अंतिम ओपिनियन पोल के अनुसार, मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के गुट और इजरायल डिफेंस फोर्स (आईडीएफ) के पूर्व प्रमुख गादी आइसेनकोट की यशार पार्टी के नेतृत्व वाले विपक्षी गुटों के बीच कड़ा मुकाबला होने के संकेत हैं। द टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर दोनों पक्ष अपने चुनावी वादों पर कायम रहते हैं तो किसी भी पक्ष को संसद में बहुमत मिलने की संभावना कम है। इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग और उनकी पत्नी मिशाल हर्जोग, देश के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-गवीर ने भी अपना वोट डाला। स्थानीय समयानुसार रात 10 बजे



मतदान खत्म होने के तुरंत बाद एग्जिट पोल आने की उम्मीद है, जिनसे नतीजों का शुरुआती संकेत मिल सकता है। वहीं, वोटों की गिनती पूरी होने के बाद आने वाले दिनों में आधिकारिक नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस बीच, बात करते हुए एक स्थानीय नागरिक ने लोगों से अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने कहा, हर किसी को बाहर निकलकर वोट देना चाहिए। 18 साल से ऊपर के सभी को आना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए और अपना वोट डालना चाहिए। एक अन्य स्थानीय नागरिक ने इस चुनाव के महत्व पर जोर देते हुए कहा, श्मेरे हिसाब से, इजरायल के इतिहास में यह सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। वहीं, इजरायल डिफेंस फोर्स (आईडीएफ) के पूर्व मेजर एरियल एवरबुच ने चिंता जताई कि इस चुनाव के नतीजे से एक राजनीतिक गतिरोध पैदा हो सकता है, जिसकी वजह से देश में दोबारा चुनाव कराने की नौबत आ सकती है। आईएएनएस से उन्होंने कहा, मुझे डर है कि कल मुकाबला टाई हो सकता है, जिससे हमें एक और चुनाव का सामना करना पड़ सकता है। मुझे लगता है कि अंत में दक्षिणपंथी गुट - जिसका नेतृत्व शायद नेतन्याहू करेंगे - जीत जाएगा, लेकिन मुझे चिंता है कि कल मुकाबला टाई हो सकता है। इजरायल की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के नेतन्याहू के तरीके की तारीफ करते हुए, एवरबुच ने हिजबुल्लाह, हमास, ईरान और हूती विद्रोहियों जैसे कई मोर्चों पर प्रधानमंत्री के रुख की सराहना की। उन्होंने कहा, ...यह कहना कि लोग खुश नहीं हैं, असल में सच नहीं है, क्योंकि जब यहूदियों के होलोकॉस्ट (नरसंहार) के बाद सबसे भयानक आतंकी हमला हुआ, तब वे ही देश की कमान संभाल रहे थे। लेकिन उस हमले के बाद, युद्ध के दौरान नेतन्याहू का रवैया बहुत सराहनीय रहा है। देखिए, कई लोग हिजबुल्लाह पर हुए पेजर हमले, हमास के खिलाफ कार्रवाई, गाजा पट्टी के 70 प्रतिशत से ज्यादा हिस्से पर इजरायल का नियंत्रण, ईरान पर हमला और हूती विद्रोहियों के खिलाफ उनके साथ हैं। इन सभी मोर्चों पर नेतन्याहू ने बहुत सख्ती और मजबूती से काम किया है। 7 अक्टूबर, 2023 को हमास के हमले के बाद यह पहला चुनाव है। 2022 के चुनावों के बाद से राजनीतिक परिदृश्य में काफी बदलाव आए हैं और मतदाताओं की प्राथमिकताओं को तय करने वाले मुद्दों में भी बड़ा अंतर आया है।

एलपीजी की कमी की अफवाहों से बढ़ी सिलेंडर बुकिंग

रोजाना 90 लाख तक पहुंचे आंकड़े, हरदीप पुरी ने किया खुलासा

(एजेंसी)

पणजी। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट के दौरान एलपीजी का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के साथ आयात के स्रोतों की संख्या 27 से बढ़ाकर 41 की। उन्होंने यह भी कहा कि देश की तेल शोधन क्षमता 2030 तक बढ़कर 30 करोड़ टन सालाना होने की उम्मीद है। पुरी ने यहां आयोजित श्29वें ऊर्जा प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सम्मेलन के दौरान अलग से संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दैनिक घरेलू एलपीजी उत्पादन 34,000 टन से बढ़कर 55,000 टन हो गया। इसके साथ ही अमेरिका और अल्जीरिया जैसे देशों से आयात बढ़ाकर खाड़ी क्षेत्र से आपूर्ति में आए गतिरोध की भी भरपाई की गई। उन्होंने कहा कि संकट की प्रकृति का पहले से अनुमान लगाना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन उससे निपटने की



तैयारी पहले से की जा सकती है। भारत ने इसी दृष्टिकोण के तहत आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत विकसित किए, जिससे संकट के दौरान देश में रसोई गैस की व्यापक अनुपलब्धता की स्थिति नहीं आई। पुरी ने कहा कि एलपीजी की कमी की अफवाहों के कारण सिलेंडर बुकिंग में असामान्य वृद्धि हुई। सामान्य तौर पर प्रतिदिन 51-52 लाख सिलेंडर की बुकिंग होती थी, जो बढ़कर करीब 90 लाख तक पहुंच गई थी। उन्होंने कहा, इतनी बड़ी वृद्धि वास्तविक खपत बढ़ने का नतीजा नहीं हो सकती है। सरकार ने जमाखोरी और सिलेंडरों की अवैध आपूर्ति रोकने के लिए कदम उठाए। राज्यों के अधिकारियों ने छापेमारी की और सिलेंडर जब्त किए, जिसके बाद बुकिंग में कमी आई। पुरी ने कहा कि भारत की तेल रिफाइनिंग क्षमता फिलहाल करीब 29 करोड़ टन सालाना है, जिसके 2030 तक बढ़कर 30 करोड़ टन सालाना हो जाने की उम्मीद है। मौजूदा रिफाइनरियों की क्षमता बढ़ाने और नई परियोजनाओं से इस विस्तार में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, रिफाइनिंग क्षमता में बड़े पैमाने पर वृद्धि से हम न केवल अपनी जरूरतों के लिए, बल्कि दुनिया के लिए भी तेल शोधन करने की स्थिति में होंगे।

पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि जहां यूरोप और पश्चिमी देशों के कुछ हिस्सों में रिफाइनिंग क्षमता घट रही है, वहीं भारत अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि यूरोप में हर साल कम-से-कम 2.5 लाख बैरल प्रतिदिन की रिफाइनिंग क्षमता घट रही है। पुरी ने कहा कि भारत में रिफाइनरियां अपनी क्षमता बढ़ा रही हैं। कुछ तीन लाख टन सालाना क्षमता वाली रिफाइनरियों की क्षमता छह लाख टन और छह लाख टन क्षमता वाली रिफाइनरियों की क्षमता नौ लाख टन तक बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि बढ़ती उत्पादन क्षमता से भारत घरेलू बाजार और विदेशों, दोनों की जरूरतें पूरी करने की स्थिति में होगा।

दिवाली से पहले खरीदारों की मौज, सोना-चांदी हुआ और सस्ता

(एजेंसी)

नयी दिल्ली। धनतेरस और दिवाली से पहले सोने-चांदी की खरीदारी करने वालों के लिए राहत भरी खबर है। पिछले कई दिनों से जारी गिरावट के बीच मंगलवार को भी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कीमती धातुओं पर दबाव बना रहा। घरेलू बाजार एमसीएक्स पर सोने में 0.43 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, और यह 1.42 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गया। वहीं चांदी 2.1 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1.91 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के करीब पहुंच गई। इस तरह, सोने और चांदी की कीमतें अपने रिकॉर्ड स्तरों से काफी नीचे आ चुकी हैं, जिससे त्योहारी खरीदारी की योजना बना रहे उपभोक्ताओं को फायदा मिल रहा है। बाजार जानकारों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर ऊंची ब्याज दरों की आशंका, कमजोर निवेश मांग और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जारी बिकवाली का असर घरेलू कीमतों पर भी दिखाई दे रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार, कॉमेक्स में



मंगलवार को सोना करीब 0.54 प्रतिशत गिरकर 4,016.60 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करता नजर आया, जबकि चांदी 2.73 प्रतिशत की गिरावट के साथ 52.855 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। पिछले कुछ हफ्तों से वैश्विक बाजार में लगातार दबाव बना हुआ है और सोना मनोवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण 4,000 डॉलर प्रति औंस के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। निवेशकों की नजर अब अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक और आगे की ब्याज दर नीति पर बनी हुई है। वहीं, वैश्विक कमजोरी का असर भारतीय बाजार में भी दिखा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर दिसंबर डिलीवरी वाला सोना करीब 656 रुपए यानी 0.46 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,42,417 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता नजर आया। वहीं चांदी में और बड़ी गिरावट देखने को मिली यह करीब 3,808 रुपए यानी 1.94 प्रतिशत टूटकर 1,91,985 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती नजर आई। दिन के कारोबार में एमसीएक्स पर सोने ने 0.43 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,42,216 रुपए प्रति 10 ग्राम का निम्नतम स्तर छुआ, वहीं चांदी ने 2.1 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,91,516 रुपए प्रति किलोग्राम का इंट्रा-डे लो छुआ। बता दें कि इस वर्ष 29 जनवरी को सोने ने 1,93,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब अपना रिकॉर्ड उच्च स्तर बनाया था। वहीं चांदी 4,20,048 रुपए प्रति किलोग्राम के ऐतिहासिक स्तर तक पहुंच गई थी। मौजूदा कीमतों की तुलना करें तो सोना अपने उच्चतम स्तर से लगभग 50,784 रुपए प्रति 10 ग्राम तक और चांदी करीब 2,28,532 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक सस्ती हो चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि शादी और त्योहारी सीजन की मांग कीमतों को कुछ समर्थन दे सकती है, लेकिन फिलहाल वैश्विक आर्थिक संकेतक और ब्याज दरों को लेकर बनी अनिश्चितता बाजार पर हावी है। विश्लेषकों के अनुसार एमसीएक्स पर गोल्ड के लिए 1,43,000 रुपए से 1,43,700 का स्तर महत्वपूर्ण प्रतिरोध (रेजिस्टेंस) है। यदि सोना इस स्तर के ऊपर टिकता है तो कीमतों में स्थिरता लौट सकती है। वहीं नीचे की ओर 1,40,000 रुपए से 1,41,000 रुपए का क्षेत्र प्रमुख सपोर्ट माना जा रहा है।

ई20 पेट्रोल के खिलाफ पैसे देकर चलाया गया अभियान, नितिन गडकरी ने किया बड़ा दावा, कहा- अब सारा शोर खत्म

(एजेंसी)

नयी दिल्ली। पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाने नीति (ई 20 पेट्रोल) को लेकर जारी बहस के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान सामने आया है। उद्योग संगठन सीआईआई (सीआईआई) के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने दावा किया कि तीन महीने पहले ई20 ईंधन के खिलाफ जो हंगामा खड़ा किया गया था, वह पूरी तरह से पैसे देकर चलाया गया एक पेड कैंपेन था। उन्होंने कहा कि अब यह सारा शोर खत्म हो चुका है और लोग इसके फायदों को समझ रहे हैं। गडकरी का यह बयान सरकार द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन की अधिसूचना जारी करने के ठीक एक दिन बाद आया है। नए नियमों के तहत अब ई100 (लगभग शुद्ध इथेनॉल) तक चलने वाले फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों को मंजूरी दे दी गई है। गडकरी ने कहा कि इथेनॉल



मिश्रण से भारत कच्चे तेल के आयात पर अपनी निर्भरता कम कर सकेगा, जिससे देश की कीमती विदेशी मुद्रा की बचत होगी। इसके अलावा, उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता से कोई समझौता न करने का भरोसा दिया। दूसरी ओर, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गोवा में आयोजित एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मीट में कहा कि सरकार का लक्ष्य 20 प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण का था और इसे आगे बढ़ाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि ई20 को लेकर फैलाई जा रही नकारात्मक खबरें एक सोची-समझी कहानी का हिस्सा हैं। कच्चा तेल आयात करना देश के चालू खाता घाटे (सीएडी) का बड़ा कारण है, जिसे बायोफ्यूल के जरिए नियंत्रित किया जा रहा है। देश में ई20 पेट्रोल पेश किए जाने के बाद से ही वाहन चालकों और उपभोक्ताओं के बीच इसे लेकर सवाल उठने लगे थे। माइलेज घटने का दावा कई वाहन चालकों ने शिकायत की थी कि ई20 पेट्रोल के इस्तेमाल से गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है। इंजन को नुकसान की चिंता पुराने वाहनों के पुर्जों और इंजन पर एथेनॉल के असर को लेकर संशय जताया जा रहा था। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि मानकों के अनुरूप ई20 से इंजन खराब होने का कोई बड़ा प्रमाण नहीं मिला है और पुराने वाहनों में ईंधन दक्षता केवल 3 से 5 प्रतिशत तक ही प्रभावित हो सकती है। सरकार ने इसे प्रदूषण घटाने और किसानों की आय बढ़ाने वाला दूरदर्शी कदम बताया है।

31 प्रतिशत गिरा स्टर्लिंग टूल्स का मुनाफा

(एजेंसी)

मुंबई। ऑटोमोटिव सेक्टर की कंपनी स्टर्लिंग टूल्स ने मंगलवार को वित्त वर्ष 27 की दूसरी तिमाही (जुलाई-अक्टूबर) के नतीजे जारी किए। कंपनी का स्टैंडअलोन मुनाफा सालाना आधार पर 31.12 प्रतिशत 13.63 करोड़ रुपए रह गया है, जो कि पिछले साल की समान तिमाही में 19.79 करोड़ रुपए था। तिमाही आधार पर भी कंपनी के मुनाफे में गिरावट दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही में यह 16.40 करोड़ रुपए था। कंपनी की ओर से दायर की गई एक्सचेंज फाइलिंग में कहा गया कि वित्त वर्ष 27 की दूसरी तिमाही में उसकी परिचालन से आय सालाना आधार पर 32.93 प्रतिशत बढ़कर 225.89 करोड़ रुपए हो गई है, जो कि पिछले वर्ष समान तिमाही में 169.93 करोड़ थी। तिमाही आधार पर भी इसमें 13.28 प्रतिशत का उछला दर्ज किया गया है। यह वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही में 199.40 करोड़ रुपए थी। कंपनी के मुनाफे में कमी की बड़ी वजह खर्च में बढ़ोतरी होना है। वित्त वर्ष 27 की दूसरी तिमाही में कंपनी का खर्च 35.16 प्रतिशत बढ़कर 210.29 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में 155.58 करोड़ रुपए था। तिमाही आधार पर भी इसमें 16.89 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही में यह 179.89 करोड़ रुपए था। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 27 की दूसरी तिमाही में कंपनी का नेट कैश फ्लो -29.25 करोड़ रुपए रहा है, जो कि पिछली वर्ष की समान तिमाही में 9.09 करोड़ रुपए था। नतीजों के बाद शेयर लाल निशान में फिसल गया। दोपहर 1.30 बजे यह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर 0.54 प्रतिशत की गिरावट के साथ 215.71 रुपए पर था। हालांकि, शेयर की शुरुआत सकारात्मक हुई थी और यह 220 रुपए पर खुला था। अब तक के कारोबार में इसका इंट्राडे हाई 227.46 रुपए था।

कर चोरी के मामलों में सीधे कार्रवाई नहीं, पहले करदाताओं की मंशा साबित करनी होगी : सीबीआईसी

(एजेंसी)

नयी दिल्ली। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा कि जीएसटी क्षेत्रीय अधिकारियों को अब कर मांग बढ़ाने के लिए धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत बयानबाजी या तथ्यों को छिपाने से संबंधित कड़े जीएसटी कानून प्रावधानों को लागू करने से पहले करदाता की कर चोरी की मंशा को साबित करनी होगी। सीबीआईसी ने एक परिपत्र में कहा कि कर चोरी की मंशा के साथ धोखाधड़ी या जानबूझकर गलत बयानबाजी या तथ्यों को छिपाने के श्विशिष्ट साक्ष्य के बिना केवल जीएसटी के भुगतान न करने के आधार पर सीजीएसटी (सीजीएसटी) अधिनियम की धारा 74(1) या धारा 74ए (5)(2) को लागू नहीं किया जा सकता है। इसमें कहा गया कि इन प्रावधानों को केवल इसलिए भी लागू नहीं किया जाएगा क्योंकि जांच के दौरान कोई विसंगति पाई गई है, क्योंकि जांच



कार्यवाही अभिलेखों की जांच करने और मामले की प्रकृति का पता लगाने के लिए की जाती है, न कि धोखाधड़ी का अनुमान लगाने के लिए। सीबीआईसी ने कहा, ऐसे में इन प्रावधानों को केवल वहीं लागू किया जा सकता है जहां जांच से इस तरह के आचरण के ठोस साक्ष्य सामने आते हैं, जिन्हें कारण बताओ नोटिस में भी स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाना चाहिए श्श् यह परिपत्र आठ अक्टूबर को आयोजित 57वीं जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद आया है, जिसमें जीएसटी कानून और नियमों को अपराधमुक्त करने के कई बदलावों पर निर्णय लिया गया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में और राज्य के वित्त मंत्रियों वाली इस परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्तियों को समाप्त करने का निर्णय लिया, जबकि अभियोजन सीमा को एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये कर दिया गया। जीएसटी कानून में बदलाव के लिए संसद की मंजूरी जरूरी है और ये अगले साल एक अप्रैल से प्रभावी होंगे, जबकि प्रशासनिक कामकाज में बदलाव परिपत्र जारी करके किए जा रहे हैं।

स्वत्वाधिकारी एक्सपर्ट टाइम्स नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक, सम्पादक जितेन्द्र कुमार द्वारा शॉप नम्बर-2 प्लॉट नम्बर-17, ग्राउण्ड फ्लोर, ब्लॉक एल-3, नियर भोला चौक, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली-110059 से प्रकाशित एवं मुद्रक दिनेश शर्मा द्वारा स्वास्तिका क्रीएशन 19 डीएसआईडीसी शेड्स, स्कीम 3, ओखला फेज-2 नईदिल्ली-110020 से मुद्रित। रजिस्ट्रेशन नं0- DLBIL/26/A3806 मो0 नं0- 9266066092

❖पीआरबी एक्ट के अंतर्गत सभी विवादों का न्याय क्षेत्र द्वारका कोर्ट दिल्ली होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित लेख अथवा समाचार से सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।